fExpoRTS OP SEA FOOD

355. DR. (MRS.) MANGLADEVI TALWAR : Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether sea food exports during 1968-69 have hit a new high ;

(b) if so, the extent of exports in terms of quantity and the foreign exchange obtained thereby during that year ;

(c) how it compares with the respective figures for the preceding three years ; and

(d) the targets of sea food exports, itemwise fixed for the year 1969-70 and the amount of foreign exchange expscted therefrom ?

THE DEPUTV MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) to (c) Yes, Sir. The comparative statement of exports during 1965-66, 1966-67, 1967-68 and 1968-69 is as follows :—

Year	Quantity (Tonnes)	Value (Rs. crores)
1965-66 . .	15295	7·06
1966-67 . .	21116	17·37
1967-68 . .	21907	19·72
1968-69 . .	26811	24·70

(d) No official target has been fixed for the year 1969-70 for the exports of seafoods.

tExHJB:TioN OF TAMIL FILMS IN CEYLON

372. SHRI M. SRINIVASA REDDY :
SHRI Y. ADINARAYANA REDDY :
SHRI S. A. KHAJA MOHIDEEN :

Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether Government's attention s been drawn to the news item published in the 'Times of India', dated June 7, 1969 (Delhi Edition) to the effect that Tamil films are being banned in Ceylon, and

•(Transferred from the 25th July, 1969.

(b) if so, whether Government propose to discuss this matter with the Government of Ceylon ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) and (b) Government have seen the news item in question. Ceylon has not imposed a ban, as such on Tamil films. The import quota for Indian films has however been reduced. The matter has been taken up with the Government of Ceylon.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

GRANT OF SCHOLARSHIPS OUT OF CENTRAL GRANTS TO STUDENTS BELONGING TO SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

श्री मानसिंह वर्मा (उत्तर प्रदेश) : उप-सभाध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के मैट्रिक के बाद कालेजों में प्रवेश पाने वाले छात्रों को केन्द्रीय अनुदानों में से छात्रवृत्तियां दिये जाने के संबंध में समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी किये गये हाल के आदेशों की ओर विधि तथा समाज कल्याण मंत्री का ध्यान दिला रहा हूं।

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE (SHRI P. GOVINDA MENON) : Sir, the main points in the recent orders are :

(1) Students who enter a course after they have completed the age of 30 will not be eligible for new scholarships.

(2) The means test which already existed for scheduled castes has been extended to scheduled tribes. Previously there were 11 slabs of income specified in the orders and now it has been simplified to two slabs. Those whose income does not exceed Rs. 360 per mensem will get full scholarships and those whose income exceeds Rs. 360 but not Rs. 500 per mensem will be paid a block grant for their tuition fees and books etc. and half maintenance charges.

(3) A merit ti st of a minimum of 45% mam has bee 1 introduced for post-Graduate schol; 1 rship.

These changes have been effected with a view to enh tnce substantially the rate of scholars) ip to the students. The Object is to dis ribute the available resources for pa; ment of scholarships *in* the most fruitfu 1 and effective manner. The total gra it available for scholarships has not bet n reduced. This matter is now being c msidered by the Parliamentary Comn ittee for the welfare of Scheduled Caste ; and Scheduled Tribes and Governmen await their report on this matter and would be willing to reconsider the whc e question in the light of the reports rt ;eived.

श्री मानसिंह वर्मा : उपसभाध्यक्ष महोदय पूर्व इसके कि मैं प्रश्न करूं मैं क्षमा चाहूंगा कि दो मिनट इसकी पृष्ठभूमि के लिये लेना चाहूंगा। अब तक जितनी भी छात्रवृत्तियां दी जाती थीं, अर्थात मैट्रिक पास करने के पश्चात् एम० ए० तक या एम० ए० के पश्चात भी जितनी टेकनिकल एजुकेशन है उस सब में, सब छात्रों को दी जाती थीं, कोई नम्बर नहीं था, कोई संख्या नहीं थी, सब को ही केन्द्रीय सरकार से छात्रवृत्तियां मिलती थीं, परन्तु अब जो नया आदेश जारी किया गया है उसमें कुछ इस प्रकार की शर्तें लगा दी गई है जैसा कि मंत्री महोदय ने अभी बतलाया कि राज्य सरकारों को यह आदेश दिये गये हैं कि वह अपने नान-प्लांड बजट में से ये छात्रवृत्तियां देंगे और उसके बाद यदि कमी पड़ेगी तो केन्द्रीय सरकार उसे पूरा करेगी और उसके लिये भी जो शर्तें अब लगाई हैं वे शर्तें पहले नहीं थीं, जिनका वर्णन मैं संक्षेप में करना चाहूंगा।

पहले शेडयूल्ड ट्राइब्ज के लिये आय का किसी प्रकार का कोई बन्धन नहीं था। शेडयूल्ड ट्राइब्ज के सभी बच्चों को छात्र-वृत्ति मिला करता थी। उनके लिये आमदनी का कोई प्रश्न नहीं था। दूसरा यह जो है कि 45 परसेंट मार्कस् वह लेगा तो उस बच्चे को छात्रवृत्ति मिलेगी, अब तक इस प्रकार का नहीं था।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आप यह जानते हैं कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से इस प्रकार की जो सहायता दी जा रही है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है, वह केवल उनकी निर्धनता, गरीबी, उनके पिछड़ेपन, को ही देख कर दी जा रही है। एक बच्चा जो कि झोंपड़ी में रह रहा है, जिसका पारिवारिक जीवन इतना पिछड़ा हुआ है, उसके लिये इतने साधन नहीं हैं कि वह दूसरे बच्चों के मुकाबिले में इतने मार्कस् ला सके। इन्हीं तमाम बातों को देखते हुये आज तक यह प्रतिबन्ध नहीं लगा हुआ था, किन्तु अब जो नई शर्तें लगाई गई हैं उसमें उसको 45 परसेंट मार्कस् लाना होगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : That is only for post-graduates.

SHRI J. P. YADAV (Bihar) : Post-matric, not post graduate.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : 45% is for post-graduate.

श्री मानसिंह वर्मा : जी हां पोस्ट ग्रेजुएट में एम० ए० भी आ गया।

दूसरी बात यह है कि अब तक जिनके अभिभावकों की, गार्डियंस की इंकम 500 रु० होती थी, या 500 रु० से ऊपर होती थी, उनको आधी छात्रवृत्ति मिलती थी किन्तु अब वह सीमा घटा कर 360 रु० से 500 रु० तक कर दी गई है।

श्रीमन्, इन शर्तों के कारण से तमाम प्रदेशों से इस प्रकार के समाचार आ रहे हैं और इस प्रकार के पत्र हमको प्राप्त हो रहे हैं कि तमाम देश के अन्दर एक . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : It appears that you do not know the exact position. The exact position is that those whose income does not exceed Rs. 360 per month will get full scholarship. There is no change and those whose income exceeds Rs. 360 but less than Rs. 500 will be paid block grant for their tuition fees.

श्री मानसिंह वर्मा : वही तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि 500 की जो लिमिट थी उसको 360 की लिमिट पर ले आये हैं। तो इन शर्तों के कारण एक गम्भीर स्थिति हो रही है। अब तक जितना काम हरिजनोत्थान का किया गया है उस सब में यदि कोई काम हुआ था तो वह शिक्षा के क्षेत्र में ही हुआ था।

और यह देखिये, बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि पूज्य बापू जी जिन्होंने अपना सारा जीवन उनके सुधार के लिये संघर्ष करने में लगाया है, उनकी जन्म शताब्दी के वर्ष में यह इनाम आज दलित वर्ग को दिया गया है। आज चारों तरफ से यह समाचार आ रहे हैं कि बच्चे अब पढ़ नहीं पायेंगे। मैं जानता हूं और मुझे अपने प्रदेश में भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्पेशल ऑफिसर बन कर काम करने का मौका मिला है, कि यदि इस प्रकार की सरकार की ओर से अनुदान या सहायता न होती तो मैं कह सकता हूं कि इतने बच्चे हमारे पढ़ नहीं सकते थे। मैं मंत्री महोदय से यह प्रश्न पूछना चाहूंगा कि अब तक जो सहूलियतें दी जा रही थीं, उनको विदड्रा करने का आधार क्या है ? क्या किसी प्रकार का क्या रिव्ह्यू कर लिया गया है क्योंकि मैं तो समझता हूं कि अब तक जो रिपोर्ट आई हैं, समय समय पर क्वेश्चन आते रहे हैं, प्रतिवेदन हैं उन सब में एक मत से यह बात स्वीकार की गई है कि अभी तक उनके सुधार में किसी प्रकार की प्रगति नहीं हुई है, जितना कार्य होना चाहिये था उतना नहीं हुआ है। अभी कल ही इन तमाम बातों को लेकर लगभग 106 संसद सदस्यों ने माननीय प्रधान मंत्री जी को स्मरण पत्र दिया है और जब वह स्मरणपत्र देने लगे तो श्रीमान्, प्रधान मंत्री जी ने आश्चर्य प्रकट किया कि मैं नहीं समझता कि यह कैसे आदेश हो गये और किस प्रकार से ऐसा हो गया, मैं इसको देखूंगी। उन्होंने इसको पुनर्विचार करने का आश्वासन भी दिया। तो मैं यह पूछना चाहूंगा कि इसका आधार क्या है, क्या समझ कर ऐसा किया गया है ? क्या राज्य सरकारों से इसके लिये परामर्श कर लिया गया था और यदि परामर्श कर लिया गया था तो क्या राज्य सरकार इसके लिये तैयार हो गयी कि हम अपने नौन प्लान बजट से यह छात्रवृत्तियां देंगे ? इन प्रश्नों का उत्तर मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा।

SHRI P. GOVINDA MENON : Mr. Vice-Chairman, as I submitted, there is a Committee of this Parliament which looks into the question of the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled lubes and that Committee is looking into this matter. If they advise me thai this should be changed and I should revi rt to the old state of affairs, I have absolutely no objection to review there things.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : He want* to know what is the basis for the change.

SHRI P. GOVINDA MENON : The basis for the change was this, Sir. The money is limited. A demand for enhancement of the rates of scholarship was there, and the demand fcr enhancement of the rates of scholarship was considered to be a good demand, and therefore we wanted to enhance the rate of scholarship , And with the amount available . . .

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal) Mr. Vice-Chairman, you asked him a legitimate question. He should tell us what would have been the financial implication. Suppose, without changing it you had met the increased demand, what extra money would have been required, so that we can judge it on that basis ?

SHRI P. GOVINDA MENON : Sir, the moneys that have been spent for the last few years are with me. The latest amount is Rs. 6.55 lakhs and it would have been much more, and I have already moved the Finance Ministry to give more grants. And I am also aware of the representations made by the hon. Members 10 the Prime Minister. *{Interruptions)* It is done for that purpose. Sir, I assure the House that in view of the discontent over the new changes which have been proposed, I am prepared to reconsider them.

SHRI K. S. CHAVDA (Gujarat) : May I know, Sir, . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P BHARGAVA) : There are other names in the list. Mr. Sundar Singh Bhandari.

SHRI MAN SIP GH VARMA : Sir,. ..

THE VICE-CH YIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) You have had your big say. If time permits, I will come back to you.

SHRI K. S. CH WDA : On a point o* order, Sir. The h»n. Minister just now said that the rate has been enhanced, that is, increased. I have got the correct ,ates; the facts are here.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) There is no point of order. Will you j lease take your seat? In the name of a j oint of order you want to ask a clarificatio t. This is no point of order. Mr. Sunda: Singh Bhandari.

श्री नेकीराम (हरियाणा) : श्रीमान् जी, आपने एक बार आनरेबल मेम्बर को अलाऊ किया फिर उनको बैठा दिया । यह कौन सी पालिसी है सरकार आपकी ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : It is no point of order. Please sit down.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान) : मेरा सवाल यह है कि इन नये आदेशों के अनुसार क्या यह बात सही है कि अभी तक स्टेट गवर्नमेंटस को जो पैसा सेन्टर की तरफ से इन स्कालरशप को मीट करने के लिये दिया जाता था, अब इन आदेशों के बाद वह पैसा, जो ओरिजिनली दिया जाता था, क्या वह नहीं दिया जायेगा?

कोई एडीशनल एक्सपेंडीचर अगर स्टेट गवर्नमेंट करेगी तो उतना ही दिया जायेगा और उस ओरिजिनल एक्सपेंडीचर को स्टेट गवर्नमेंटस को बीयर करना पड़ेगा । अगर स्टेट गवर्मेंटस उसको बीयर नहीं कर सकती हैं तो, उसमें सेन्टर हेल्पलेस है, क्या इस आदेश का यह अर्थ है ?

दूसरे, क्या पोस्ट ग्रैज्युएट्स स्टुडेन्ट्स में 45 परसेन्ट से ज्यादा मार्क्स प्राप्त करने वालों के बारे में कोई संख्या का स्टेटिस्टिक्स गवर्नमेंट के पास है और क्या सरकार उस आधार पर इस बात का कोई संकेत देगी कि स्कालरशिप प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या 45 परसेन्ट से ज्यादा की थी और क्या 45 परसेन्ट का रेस्ट्रिक्शन लगाना किसी भी प्रकार से ओवर-आल पोस्ट ग्रेज्युएट स्टुडेन्ट्स की संख्या में मैटीरियली एफेक्ट नहीं करेगा ?

हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि जैसा मिनिस्टर कन्सर्न्ड ने स्वयं यह माना है कि एक कमेटी इस सारे क्वेश्चन को रेव्यू कर रही है, रिवाइज कर रही है, अपनी रिकमेन्डेशन देने वाली है तो "इन व्ह्यू आफ द क्रिटिसिज्म एन्ड द आब्जेक्शन्स रिसीव्हड्" मैं चाहूंगा मंत्री महोदय हियर एन्ड नाऊ इस बात की घोषणा करें कि वह आदेश तब तक के लिये स्थगित होंगे जब तक कि उस कमेटी की रिकमेन्डेशन आकर ब्रेडबेयर उस पर डिसकशन होकर आगे के लिये उसके बारे में कोई चाक्ड आऊट प्रोग्राम तैयार नहीं हो जाता है । थ्री स्पेसिफिक क्वेश्चन्स ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : Three in one question.

SHRI P. GOVINDA MENON : Sir, I will answer the last question first. In the light of the discontent against this order, which I thought would be good, in the light of the view that this should be stayed till the report of the Advisory Committee is received, I am prepared to do it. But this has been done in order to benefit the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

The question was asked why the State Governments arc being asked to find this amount. I will explain it. This is a Centrally-sponsored Plan scheme, and in a Centrally-sponsored Plan scheme the rule is that after the Plan it becomes committed expenditure, which the State Government concerned has to meet. And this committed expenditure will be looked after by the Finance Commission. B-.'.' if the State Governments are not able to do that, we will consider what we can do. An amount of Rs. seven crores will be required. I have taken up the question with the Ministry of Finance, that is, with the Prime Minister, whom a large number of representatives of the communities are reported to have met yesterday. I want to assure the House that this has been done thinking, that this will do good to the communities.

[Shri P. Govinda Menon]

The proposal is there to enhance the scho" larship to those who are undergoing technical courses by ioo per cent, and by 50 per cent, in the case of academic courses. This matter also is awaiting the clearance by Finance. The hon. Member requested me to study the whole matter. I agree to do so.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: I raised the question about 45 per cent,

SHRI P. GOVINDA MENON: On that matter I have no figures with me now.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P-BHARGAVA) : I do not think that any further questions are necessary because he is staying the order and the *status quo* will remain. Next in the list is the name of Shrimati Sarla Bhadauria.

श्रीमती सरला भदौरिया (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं मंत्री महोदय के वक्तव्य से चिंता में पड़ गई थी लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने कहा कि हम सारा आदेश वापस ले लेंगे और हम उनको तरक्की की पूरी सुविधा देंगे । मेरा तो यह विश्वास है कि कुछ विशेष अवसर के द्वारा ही उनमें तरक्की लायी जा सकती है। जो आंकड़े बताये हैं मंत्री महोदय ने कि साढ़े छ लाख रु० दे चुके हैं, तो मिक कोट से जो अनुदान दिया गया वह कम ही है । मुझे यह कहना है कि मंत्री महोदय राज्य सरकारों का बहाना लेकर या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों का बहाना लेकर कहीं फिर गुमराह न हो जाये । अभी तक इतने दिनों का जो मेरा अनुभव है उसके अनुसार सरकार जिस बात को अभी तक कहते आई है बाद में उसको बदल देगी । मुझे आशंका है कहीं ऐसा ही न हो जाये अभी यहां फ्लोर में कहने के बाद, कहीं कमेटी में बैठने के बाद, वह बदल न जायें । दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि अगर खजाने में रुपयों की कमी है, पैसों की कमी है केन्द्रीय सरकार के पास, तो यह जो संसद् सदस्यों का वेतन भत्ता बढ़ाया जा रहा है उसे बंद किया जाय और मंत्रियों की विलासता को कम किया जाय । हमें देश के हित को सामने रखना है और समाज में जो पिछड़े हुए लोग हैं उन्हें सब के बराबर में लाना है । यह सरकार जो अपने को समाजवादी सरकार कहती है, जो इस देश में समाजवादी व्यवस्था लाना चाहती है, उसने इन पिछड़े हुए लोगों को जो भी अधिक से अधिक देने का वचन किया उससे भी अधिक अनुदान उनको बेहतरी के लिए दिया जाना चाहिये । इस तरह के काम में कोई भी कमी किसी तरह की करना अनुचित है ।

मैं तो यह कहना चाहती हूं कि वास्तव में एक ही उदाहरण उनकी तरक्की का हम देश के सामने ला सकते हैं अगर हम उनमें से किसी को राजदूत बनाकर या वैज्ञानिक बनाकर दिखलायें । हमने इतने दिनों तक इन लोगों को विशेष सुविधा दी है, लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि हरिजनों और आदिम जातियों में से अभी तक एक भी वैज्ञानिक बड़ा वैज्ञानिक नहीं निकल पाया है । तो मैं सरकार से कहना चाहती हूं कि इतनी विशेष सुविधा देकर आपने इन लोगों की क्या तरक्की की है । आप इन लोगों का सामाजिक स्तर उठाइये, सुसंस्कृत बनाइये और सुशिक्षित बनाइये ताकि वे आगे चलकर जिम्मेदारी के पदों पर पहुंच सकें । यह बात मैं केन्द्रीय सरकार से चाहती हूं ।

SHRI P. GOVINDA MENON : The hon. Member wanted me to say once again that I won't change my promise after going out of this House. Suppose I repeat my promise once again; then also I can change it. I made it on the floor of the House on the representation made by Mr. Bhandari that this Order should be stayed until after the matter is fully discussed and reported upon.

I committed a mistake in my previous answer; I said six lakhs but it is six crores.

SHRI KOTA PUNNAIAH (Andhra Pradesh) : Sir, let me offer my thanks to the hon. Minister first for staying this circular. It is deplorable that the Deputy Minister once answered a question whether these scholarships provided a means of livelihood for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. That hurt many people and created apprehensions about this circular. I want to know specifically whether this circular would not arrest the progress of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes when they have not made adequate progress up till now. I want specific answers to these two points that I have raised.

SHRI P. GOVNDA MENON : Sir, that is a matter ol" opinion but since the opinion of friend; in this House is that this should be stj ^ed I am staying that. So that does not iurther arise.

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, इस संबंध में जब मंत्री जी विचार विनिमय कर रहे हैं तो मैं यह चाहता हूं कि मंत्री जी अपने सम्मुख शुरू से जब से यह समाज कल्याण की योजना चली है उसको अपने सामने रखें । जब यह योजना शुरू शुरू में चली थी तो उस समय यह योजना थी कि इन लोगों को पैसे की गारन्टी दी जानी चाहिये । सामान्य रूप से यह योजना थी कि जितने भी हरिजन विद्यार्थी हैं, उनको स्कालरशिप मिलेगी, उनको फ्रीशिप मिलेगी और उनको पढ़ने के संबंध में सारी सहुलियतें मिलेंगी । हमारी तो उत्तर प्रदेश में यह मांग थी कि इन लोगों के लिए खाने का इंतजाम भी किया जाना चाहिये । अगर हम विद्यार्थियों को फ्रीशिप करते हैं और उनके पास खाने को न हो तो वे पढ़ने कहां जायेंगे ? इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहले उनके लिए खाने का प्रबन्ध किया जाना चाहिये । तो मैं यह चाहता हूं कि पहले तो सरकार यह बतलाये कि यह जो कमेटी बनाई गई है उसमें कौन कौन मेम्बर है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री महावीर प्रसाद भार्गव) : यह चीज तो रिकार्ड में अवेलेबिल है ।

श्री राजनारायण : अगर माननीय मंत्री जी यहां पर बतला देंगे तो इसमें उन्हें आपत्ति नहीं होनी चाहिये कि इस कमेटी में कौन कौन मेम्बर हैं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री महावीर प्रसाद भार्गव) : इसमें दोनों हाउसों के मेम्बर हैं ।

श्री राजनारायण : इससे मैं यह समझ पाता हूं कि जो लोग इसमें है वे सही तौर पर हरिजनों और पिछड़े हुए लोगों को उठाना चाहते है या नहीं और उन्हें विशेष सुविधा देकर दूसरे लोगों के मुकाबले में लाना चाहते हैं या नहीं । यह बात ठीक है कि आप स्टे आर्डर कर देंगे, लेकिन इससे होगा क्या ? मैं यह कहना चाहता हूं कि हरिजनों की पढ़ाई के लिए, उनके बच्चों को भोजन दिलाने के लिए आज यह सरकार विचार करने जा रही है या नहीं ?अगर सरकार उनको पढ़ाई और भोजन का प्रबन्ध नहीं करती है तो उनके लिए आर्थिक समस्या खड़ी हो जायेगी जिसकी वजह से वे उन्नति नहीं कर सकेंगे । इसलिए आपने जो नया आर्डर निकाला है उसको आप निकाल दीजिये ।

एक बात मैं और जरूरी कहना चाहता हूं कि यह जो परसेन्टेज की बात है, उन्हें इंसेंटिव देने की बात है, यह उनको परिश्रम करने के लिए प्रेरणा दे सकता है । लेकिन जो विद्यार्थी 50 परसेंट मार्क पाये या फर्स्ट डिवीजन पाये तो उसको कोई स्पेशियल सहुलियत दी जानी चाहिये । अगर आप ऐसी कोई चीज अलग से करते है तो मैं उसको मान सकता हूं । अगर यह जो 60, 50 प्रतिशत मार्क पाये उसे कुछ दिया जाय या न दिया जाय, यह बात मैं गलत मानता हूं । खाना और फ्रीशिप तो उन्हें मिलेगा ही लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई लड़का अच्छे नम्बर लाता है तो उसको अतिरिक्त सहायता या सहुलियत दी जानी चाहिये ; आप इस चीज के लिए कुछ अतिरिक्त नम्बर रख सकते हैं कि इतने नम्बर पाने वाले लड़के को यह यह सहुलियत मिलेगी । अगर आप इस तरह की बात करते हैं तो इससे हरिजन लड़कों को अपनी प्रतिभा बढ़ाने में सहायता मिलेगी । यह तो दृष्टि का सवाल है ।

मै माननीय मंत्री जी से अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि यह प्रश्न टेक्नलिटी का नहीं है, यह प्रश्न केवल सरकारी खजाने का नहीं है । यह प्रश्न तो केवल दृष्टि का है । अगर हमारी दृष्टि विकास की होगी तो हम इन लोगों का विकास कर सकते हैं । जिस तरह से प्रथम, द्वितीय, तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में लोगों का विकास हुआ है क्या इसी तरह से इन लोगों का भी आगे विकास होगा । तो

[श्री राजनारायण]

मैं यह जानना चाहता हूं कि इन लोगों का किस दृष्टि से विकास किया जायेगा । आज तक पंचवर्षीय योजनाओं से जिस समाज का विकास हुआ है क्या उन्हीं का आगे भी विकास होगा या जो समाज के निचले वर्ग हैं, जो दबे पड़े हुए हैं उनका भी विकास होगा । तो यह दृष्टि का सवाल है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस दृष्टि से इस चीज को देखेगी कि जो समाज के अन्दर निचले हिस्से के लोग हैं उनका उत्थान किया जायेगा । क्या उन्हें विशेष सुविधा देकर शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में या चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उन्हें देश की अन्य जनता के मुकाबले खड़ा करने के लिए हर तरह की सहुलियत देगी या नहीं ? अगर सरकार की इस तरह की दृष्टि नहीं है तो चाहे वे कितने ही स्कूल खोल दें, कितनी और चीज उनके लिए कर दें, उनमें अनेक पेचकशी निकल सकती हैं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : Mr. Rajnarain, I have already pointed out that this is not a debate. This is calling attention. A statement has been made by the Minister. If you want any clarification about it, please seek it.

श्री राजनारायण : वही तो श्रीमन्, मैं कह रहा हूं । क्या सरकार की दृष्टि इस तरह की है कि जो सामाजिक स्तर से पिछड़े हुए लोग हैं उनका सामाजिक स्तर आगे बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम उनको शिक्षित किया जायेगा और उनको शिक्षित करने के लिए किसी तरह का प्रतिबन्ध नहीं लगाया जायेगा । मैं चाहता हूं कि सरकार इस तरह की दृष्टि अपनाये मगर मैं देखता हूं कि वह इस तरह की दृष्टि अपनाने के लिए तैयार नहीं है ।

SHRI P. GOVINDA MENON : I do not want to enter issue with the hon. Member on the generalisations which he made with respect to the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. He raised a pointed question regarding feeding. I understand that Harijan students living in hostels are already entitled to higher rates of scholarship. With reg* pect to the other matters I very respectfully submit to the House that having constituted a Committee of both Houses of Parliament and having promised to the House that we will abide by the advice of this Committee and having categorically stated that till their advice comes the new order will be stayed and the old order will continue to prevail, I now say further that it low be my attempt to dec that scho-ps. post-matric and otherwise, to the Hwijan and Girijan students are enhanced to the possible extent to which finances will permit.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P-BHARGAVA) : Just one minute. I have still got ten names before me and if we go on the way we have been proceeding it will take a long time. If hon. Members have still clarifications to seek, I will call out their names one by one and they can put a short question. Then we can finish this by one 'o clock bat if hon. Members go on expressing their opinion it will not be possible to finish this.

SHRI P. C. MITRA (Bihar) : I would like to know whether it is not a fact that the Harijan students used to get free (tuition irrespective of their income and, if so, why is this new procedure of granting them tuition fee only if their income is above or below Rs. 360 or Rs. 500 thought of ?

श्री राजनारायण : श्रीमन्, हमारे सवाल का क्या हुआ ?

सेवानियोजन तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जय सुख लाल हाथी) : वह हो गया । उसको देखेंगे ।

SHRI P. GOVINDA MENON : The question and the answer relate to post-matric matters. Now, with respect to UHIV' below the matriculation classes, the freeship arrangements continue.

SHRI B. T. KEMPARAJ (Myore) : I want to know from the Minister whether there is any income slab fixed in the States of Kerala, Andhra and Tamil Nadu in the case of Scheduled Caste and Scheduled Tribe students for the payment of grants sanctioned for giving educational facilities to them. My second question is this. The hon. Minister has used the word "discontent" twice. It is due to the discontent of the majority of Members that he is issuing the present circular. Therefore, I request him, let it not lie with discontent, but with pleasure. He may see that the circular is clarified and the benefits extended without any income limit.

SHRI P. GOVINDA MENON : I used the word "discontent" in the sense of disagreement and because there is disagreement with respect to the new order, I have, with gm t pleasure, stayed the operation of the ne- f order.

SHRI B. T. KE IPARAJ : What about the first part of m question ?

SHRI P. GOVII DA MENON : I want notice.

THE VICE-CH. JRMAN (SHRI M. P-BHARGAVA) : He has no information.

SHRI K. S. C HAVDA : In view of the fact that the States have never used fully the fifty per t ;nt grant given to them for pre-matric education for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and in view of the fact that th (percentage of literacy among them is noi more 10.27 and 8.51 respectively, may I know whether Government will introduc the pre-matric scholarship scheme like post-matric scholarship scheme for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to promote education among them and 'ring them on par with the rest of the po >ulation of our country ? Secondly, with reg rd to regulation 6 (2), *i.e.*, 45 per cent n arks, may I know, Sir, how the Governme t will deal with that ?

SHRI P. GOVINDA MENON : With respect to pre-ma ric matters, my information is, subject o correction—if I made a mistake it is wi h respect to the several States—that tuitioj is free and, therefore, this question does rot arise. This question is with respect to post-matric scholarships and other things.

SHRI K. S. CHAVDA : My question relates to pre-rnat ic scholarships and not free tuition.

SHRI P. GOV: NDA MENON : Other amounts are alsc given in some other States I know of.

SHRI KESAVA N (THAZHAVA) (Kerala) : The Bud ret allotment for this purpose is not r,u ficient to meet the expenses. May I :now from the hon. Minister whether l,e has already made any demands for high r amounts and, if not, may I know whetl er he would be making a demand for higl er amounts to meet the expenditure?

SHRI P. GOV NDA MENON : I am satisfied that the post-matric scholarships now being given, particularly to students in technical institutions, are not sufficient and, therefore, I have raised the question of enhancing the quantum of postmatric scholarships and the matter is pending with the Finance Ministry.

SHRI GODEY MURAHARI (Uttar Pradesh) : I should like to know from that Minister whether this order was given at the instance of the Ministers or it was done by some officers of the Ministry. It only shows the attitude of those who are administering the Social Welfare Department. I would like to know whether it was a ministerial decision. Another thing I would like to know. In view of the fact that a Parliamentary Committee is already possessed of these issues, why was this kind of order issued at all, when it is already going into these matters? I would like to know also whedier it is not proper that we should consider increasing these grants to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe students, instead of trying to curtail it or trying to adjust whatever we want to do within the funds available. It only shows the attitude of the persons administering it. I should like to know whether it was done at the level of the Ministers or at the level of the officers. If it was done at the level of the officers, I would like to suggest to the Minister that he should have such officers who have a proper attitude towards this kind of things.

SHRI P. GOVINDA MENON : This matter is being considered and I agree with him that an enhancement is necessary. As regards the order I take full responsibility for the order.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जिस आर्डर पर आज हमारे सदन में एतराज हो रहा है उस पर मंत्री महोदय ने स्वयं कभी विचार किया है क्या । जिन हरिजन और गिरिजन लोगों को शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिल रही है उनको सहायता प्राप्त करने से रोकने के लिये ही उनके विभाग के लोगों ने ऐसा आर्डर दे कर के ऐसा किया । इसका सबूत दो बातों से प्रमाणित हो जाता है । एक तो यह है कि उन पोस्ट ग्रैज्युएट स्टूडेंट्स को स्कालरशिप मिलेगा जिन को परीक्षा में 45 प्रति शत अंक प्राप्त हों । आप दिल्ली युनिवर्सिटी को छोड़ दीजिये । बाकी प्रदेशों में एक एक युनिवर्सिटी में जो बी०ए०

[श्री जगदम्बी प्रसाद यादव]

पास करने वाले लड़कों को मार्क्स मिलते हैं उनको आप देखिये । वहां पर आप देखेंगे कि जनरली जो और स्टूडेंट्स हैं और जिन के मार्क्स 45 परसेंट से ऊपर हैं उनकी संख्या बहुत कम है । हरिजन स्टूडेंट तो कोई बिरला ही होगा जिस के मार्क्स 45 पर सेंट से ऊपर होंगे । इससे प्रतीत है कि ऐसा इस लिये किया गया है जिस से किसी हरिजन या गिरीजन विद्यार्थी को स्कालरशिप मिलें । दूसर राज्य सरकारों की ओर से हरिजन और अन्य दूसरे पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को मैट्रिक के नीचे स्कालरशिप दिया जाता है । इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की ओर से सारे स्कूलों को लिख दिया गया कि हरिजन विद्यार्थियों की पढ़ाई फ्री कर दी जाय और उनको जो खर्चा पड़ेगा वह राज्य सरकारें वहन करेंगी । और दूसरी सरकारों के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जहां तक बिहार सरकार का प्रश्न है मेरी यह निजी जानकारी है कि वहां जिन स्कूलों ने हरिजन विद्यार्थियों की शिक्षा को फ्री किया उनका पेमेंट सरकार की ओर से नहीं हुआ और उसके कारण बहुत स्कूल वालों को कहना पड़ा कि हम हरिजनों को फ्री पढ़ाने में असमर्थ हैं । तो मेरा यह चार्ज है सरकार पर कि सरकार की यह चाल है और सरकार ने जान बूझ कर . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री महावीर प्रसाद भार्गव): चाल तो है, लेकिन आप का क्वेश्चन क्या है ?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : यही क्वेश्चन है कि इस षड्यंत्र पर स्वयं मंत्री जी ने विचार किया या नहीं या जो विभाग से सूचना आ गई उसी के अनुसार उन्होंने उत्तर दे दिया ।

SHRI P. GOVINDA MENON : Mr. Vice-Chairman, Sir, *prima facie* I thought that the three points in the order would be considered to be acceptable. For example when I said that a person who is above the age of thirty years should not be entering any • post-matric course for the first time and claim a scholarship, I thought there is nothing wrong in it,

SHRI GODEY MURAHARI : Why? Most of them may be of thirty years.

SHRI P. GOVINDA MENON : That is why I used the words *'prima facie"* Regarding the means test, I thought that there would be no objection if persons, whose parents earn a certain income above a certain level, are not getting post-matric sholarships. I thought it would be giving an advantage to those who are placed in such a fortunate circumstance. Regarding the merit test of 45 per cent, Members here say that very few students belonging to this community get more than 45 per cent and I accept it and if

that is so, that portion of the order is 1 P.M. wrong. In any event after this order

was issued the Committee about which I spoke earlier has taken notice of it and is considering it, and I again repeat that I would await their proposal.

SHRI P. GOVINDA MENON : That is a

श्री गणेशी लाल चौधरी (उत्तर प्रदेश) : अब तक प्रिमैट्रिक एज्यूकेशन स्टेट गवर्नमैन्ट के पास

श्री बी० एन० मंडल (बिहार) : क्या यह बात सही है कि जो आर्डर सरकार का निकला आदिवासी स्टुडन्ट्स के बारे में इसको लेकर कोई बहुत बड़ा आन्दोलन मनीपुर में खड़ा हुआ है और कलही स्टूडेन्ट्स जो इसके लिए डिमांस्ट्रेशन कर रहे थे, एजीटेशन कर रहे थे, उनको लाठियों से पीटा गया है ?

new question of policy which does not arise from this. I would like to have time to consider it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : Have you any information?

SHRI P. GOVINDA MENON : I have no information.

SHRI BHUPESH GUPTA : He should have this information. It is in the Hindustan Standard again dated 30th July. Anyway, first of all it remains to be explained how this order or regulation came to be issued so light-heartedly. Now he says it is under consideration of the Committee of Parliament. May I know why leading members of the Scheduled Caste community were not consulted by the

Minister before iss ling this kind of order? secondly, I should like to know whether we have an assuran ;e that this order would be forthwith withdrawn.

THE VICE-CH vIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : f e has stated.

SHRI BHUPES H GUPTA : It should be done. Now it is surprising. On the one hand we ^;e in the paper that the Cabinet has deci< Led to extend the period of safeguards b> another ten years, and rightly so, as far as Scheduled Castes aie concerned. At the same time we find that they ar | issuing such an order despite the recorr; ncndation of the Committee on Untoi ^liability which has a devastating findii js against the manner in which the < institutional obligations are being implemented. The position is this. Here it L- not a question of marks and other thing:. Here it is a question of helping the members belonging to the Scheduled Caste.* and backward communities to come up, of giving them extra assistance.

THE VICE-Cri AIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : He has explained the position.

SHRI BHUPESH GUPTA : He has explained nothir %. It may be a few lakhs or a crore >f rupees. The Perumal Committee has pointed out that the money sanctioned by the Government is not even spent by the v i.rious Departments and Ministries, meant for the welfare of the Scheduled Castes and backward communities. You will >e surprised the Perumal Committee says 1 hat despite the Untou-chability Law on y IOOO prosecutions have been obtained ever since the Untouchabi-lity Law come ii to being.

Now take the case of Civil Service. How many Scheduled Caste people have got employment lere ? Somehow or other a situation is ere: ted by which they do not get their due sha e, do not get the promotions they desen e, and always there is a back-log.

I should there ore like to make the following suggestii n that the hon. Minister should immedial ;ly convene a meeting of all leaders be longing to the Scheduled Castes and Sch duled Tribes and discuss the matter on th I basis of the joint letter which they have submitted to the Prime Minister dated he 30th July on this very subject, and rel .ted subjects should be discussed. Since the Minister said that he is personally responsible, I am not going to blame any officer at the moment because I am concerrned with the Minister here, but surely the decision has been taken with a bureaucratic outlook; humane outlook is not seen in that order. It is an administrative, cruel, soulless order which disregards the realities of our life and the anguish of millions and millions of the people belonging to the Scheduled Castes and backward communities. I therefore demand that a meeting of the leading members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes readily available in Parliament be immediately called by the hon. Minister and the whole thing be thrashed out. What is more, the entire responsibility must be borne by the Centre and it is no use passing it on to the States. The constitutional obligations must be carried out with a view to promoting the welfare of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the backward communi ties, and the Centre not only must find the money but it must at the same time, in consultation with the accredited representatives of those communities, formulate a correct policy and set up a proper machinery for the implementation of such policy.

SHRI P. GOVINDA MENON : The only statement which the hon. Member made about this matter was that it was a light-hearted order. I do not think so. It was a considered order. But in deference to the opinion expressed in the House I am staying it.

PAPERS LAID ON THE TABLE

THIRTY-SIXTH ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS (1967-68) OF THE INDIAN STATISTICAL INSTITUTE, CALCUTTA

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI JAISUKH-LAL HATHI) : Sir, on behalf of Shrimati Indira Gandhi, I beg to lay on the Table a copy of the Thirty-sixth Annual Report and Accounts of the Indian Statistical Institue, Calcutta, for the year 1967-68, together with the Auditors' Report on the Accounts. [Placed in Library. *See* TMo. LT-1431/69.]

LETTER FROM THE PRESIDENT OF PAKISTAN

SHRI JAISUKHLAL HATHI : Sir, on behalf of Shri Dinesh Singh, I also lay on the Table a copy of letter dated July 26, 1969, from General Agha Muhammad Yahya Khan, President of Pakistan, to the Prime Minister of India. [Paced in Library. *See* No. LT-1515/69.]